

सरकारी वित्त 2024-25: अर्ध-वार्षिक समीक्षा

हर्षिता यादव, आयुषी खंडेलवाल, कोवुरी
आकाश यादव, रचित सोलंकी, अनुप के सुरेश,
समीर रंजन बेहरा और अत्रि मुखर्जी द्वारा ^

केंद्र और राज्यों दोनों के मामले में, बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में सकल राजकोषीय घाटा 2023-24 की पहली छमाही की तुलना में 2024-25 की पहली छमाही में कम हुआ, जिसका मुख्य कारण मजबूत प्राप्तियां, उनके राजस्व व्यय वृद्धि में कमी और पूंजीगत व्यय में कमी है। इससे उन्हें 2024-25 की दूसरी छमाही में पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय गुंजाइश मिलती है, जो व्यय की गुणवत्ता में महामारी के बाद के लाभ को बनाए रखने और मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं का समर्थन करने में सहायता करेगी। कई राज्यों ने अपने 2024-25 के बजट में रियायतों की घोषणा की है; इस तरह के खर्च से संसाधन महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर हो सकते हैं।

परिचय

विकसित भारत की दिशा में एक विस्तृत प्रक्षेपवक्र प्रस्तुत करके भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक मध्यम अवधि का रोडमैप तैयार किया है। रोजगार, कौशल, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान देने के साथ, बजट का उद्देश्य विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधनों का आवंटन सुनिश्चित करते हुए उच्च विकास दर को बनाए रखना है। बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर जारी रखते हुए, बजट 2024-25 ने पूंजीगत व्यय के लिए ₹11.11 लाख करोड़ (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान किया था, जो 2023-24 (अनंतिम खाते, पीए) में हासिल जीडीपी के 3.2 प्रतिशत से अधिक है। दूसरी ओर, राजस्व व्यय को 2023-24 (पीए) में जीडीपी के 11.8 प्रतिशत से मामूली रूप से घटाकर 2024-25 (बजट अनुमान, बीई) में जीडीपी के 11.4 प्रतिशत करने का बजट बनाया गया था, जिससे सरकारी व्यय की समग्र

गुणवत्ता में वृद्धि हुई। इसके अलावा, राज्यों के पूंजीगत व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए, पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत आवंटन बढ़ाया गया। कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट का लक्ष्य 2024-25 में राजकोषीय समेकन करना है, जो 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से नीचे जीएफडी के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। राज्यों ने भी 2024-25 में राजकोषीय समेकन के लिए प्रयास किया है, 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत के समेकित जीएफडी का बजट बनाया है।

कर और गैर-कर दोनों स्रोतों से प्राप्त होने वाले केंद्र के राजस्व संग्रह में 2024-25 की पहली छमाही में उछाल आया, जो मुख्य रूप से आयकर, माल और सेवा कर (जीएसटी) और रिजर्व बैंक द्वारा अधिक अधिशेष हस्तांतरण के कारण हुआ। मजबूत प्राप्तियां और अपेक्षाकृत स्थिर सरकारी खर्च के कारण, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में केंद्र का जीएफडी पिछले एक दशक में सबसे कम था। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियां में वृद्धि कर राजस्व के कारण हुई, जबकि केंद्र से गैर-कर राजस्व और अनुदान में कमी आई। व्यय के मोर्चे पर, राज्यों ने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान राजस्व व्यय की गति को बनाए रखा, जबकि उनके पूंजीगत व्यय में गिरावट आई।^{1,2}

लेख का शेष भाग इस प्रकार संरचित है: खंड II, 2024-25 की पहली छमाही के लिए केंद्र और राज्यों (तिमाही आवृत्ति पर) की प्राप्ति और व्यय का विश्लेषण करता है। खंड III, केंद्र और राज्यों के लिए प्रमुख घाटा संकेतकों और उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित है। खंड IV, 2024-25 की पहली छमाही के लिए सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य) वित्त पर अनुमान प्रस्तुत करता है। खंड V, समापन टिप्पणियों को प्रस्तुत करता है।

II. पहली और दूसरी तिमाही में राजकोषीय परिणाम

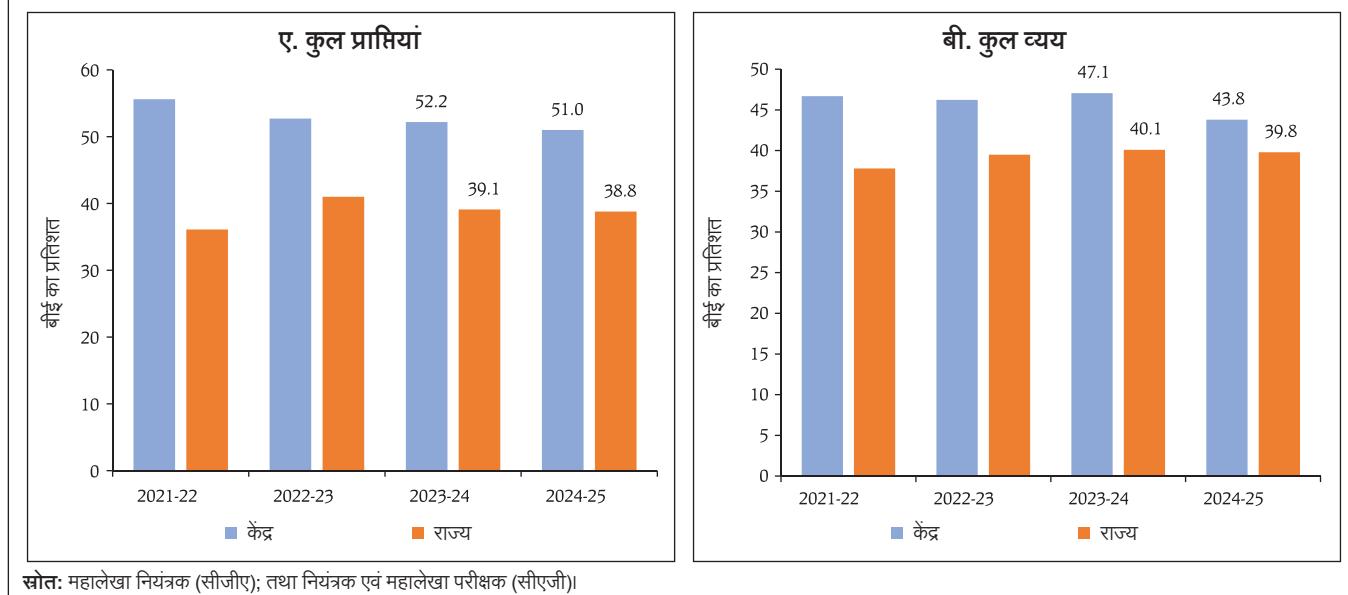
2024-25 की पहली छमाही के दौरान, केंद्र सरकार ने अपनी कुल बजट प्राप्तियों का 50 प्रतिशत से अधिक एकत्र किया, जो हाल के दिनों में देखी गई प्रवृत्ति के अनुरूप है। वर्ष-दर-वर्ष (व-व) आधार पर, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान कुल प्राप्तियां 15.5 प्रतिशत बढ़ीं। दूसरी ओर, केंद्र का कुल व्यय 2024-25

¹ यह डेटा 22 राज्यों से संबंधित है, जिनके लिए अप्रैल-सितंबर 2024 के डेटा उपलब्ध हैं। जीएफडी-जीडीपी अनुपात का अनुमान उन्हीं 22 राज्यों के जीएसडीपी डेटा का उपयोग करके लगाया गया है।

² केन्द्र तथा राज्यों की अर्धवार्षिक तथा त्रैमासिक वित्तीय स्थिति पर विस्तृत विवरण परिशिष्ट सारणी (I से IV) में दिया गया है।

^ यह लेख श्रीमती रेखा मिश्र के समग्र मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। लेखक भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

चार्ट 1: पहली छमाही में कुल प्राप्तियां और व्यय

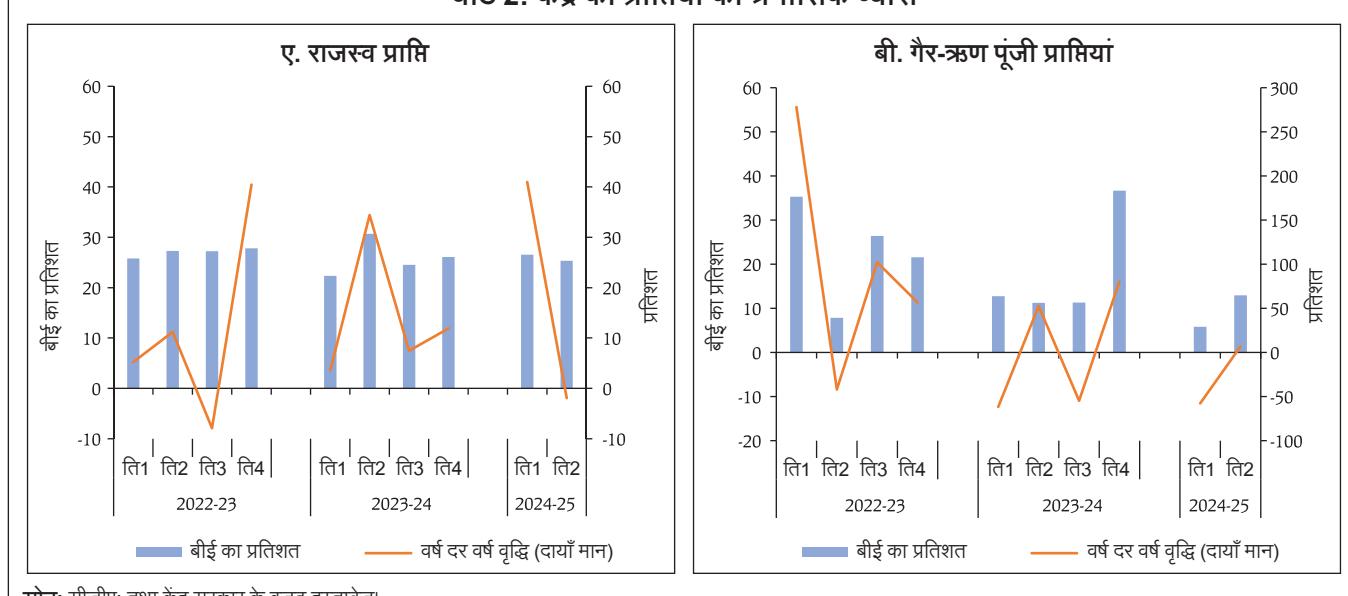


की पहली छमाही में बजट अनुमान के 50 प्रतिशत से कम था, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान देखे गए पैटर्न के अनुरूप था (चार्ट 1ए)। राज्यों का जीएफडी 2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 43.9 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में मामूली रूप से कम था, मुख्य रूप से कुल व्यय में मंदी के कारण क्योंकि राज्यों ने 2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान के 40.1 प्रतिशत की तुलना में बजट अनुमान का 39.8 प्रतिशत खर्च किया (चार्ट 1बी)।

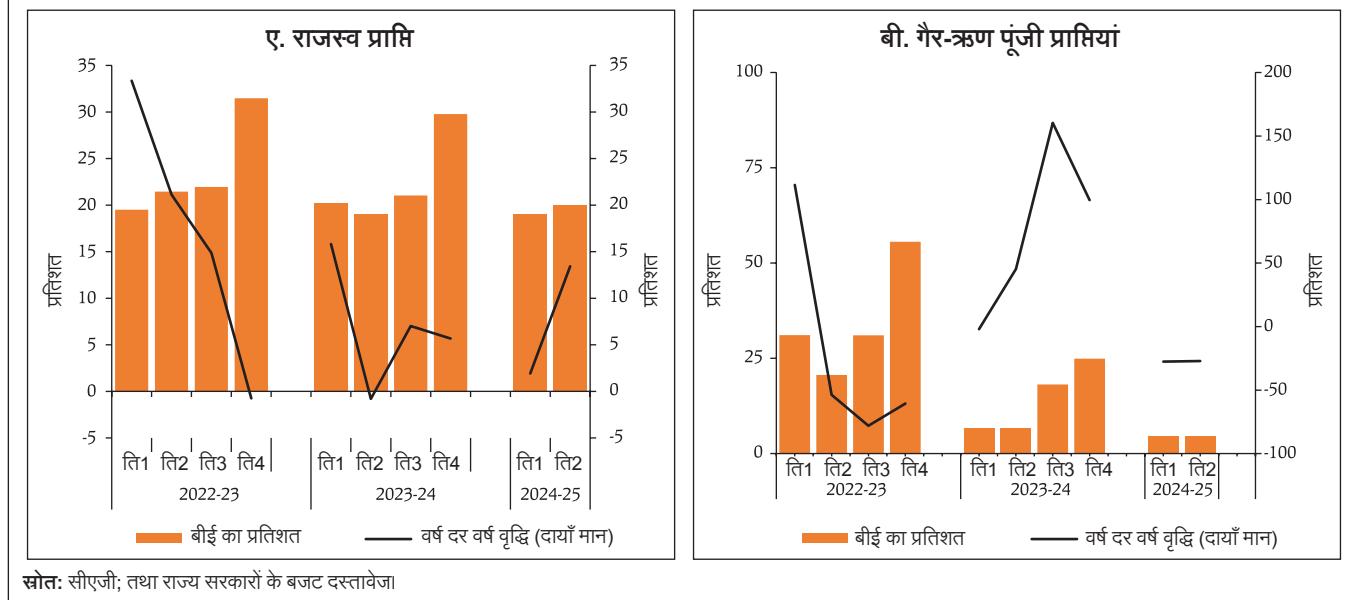
ए. प्राप्तियाँ

केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 16.1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ मजबूत रहीं। 2024-25 की पहली तिमाही में, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 41.0 प्रतिशत रही, जो कि मजबूत कर वसूली के साथ-साथ रिजर्व बैंक द्वारा 2.1 लाख करोड़ रुपये के बड़े अधिशेष हस्तांतरण के कारण हुई। 2024-25 की दूसरी तिमाही के दौरान, प्रत्यक्ष कर वसूली में गिरावट के कारण राजस्व प्राप्तियों में 2.0 प्रतिशत की कमी आई

चार्ट 2: केंद्र की प्राप्तियों का त्रैमासिक व्यौरा



चार्ट 3: राज्यों की प्राप्तियों का त्रैमासिक व्यौरा



स्रोत: सीएजी; तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

(चार्ट 2ए)। 2024-25 की पहली तिमाही में गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों का प्रदर्शन धीमा रहा, लेकिन 2024-25 की दूसरी तिमाही में इसमें सुधार दर्ज किया गया (चार्ट 2बी)³

राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2024-25 की पहली छमाही में 7.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2023-24 की पहली छमाही में 7.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 1.9 प्रतिशत और 13.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कर राजस्व, जो 2024-25 की पहली छमाही के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 85.7 प्रतिशत था, ने 2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 16.4 प्रतिशत और 7.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। राज्यों की गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियां⁴ 2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही दोनों में कम हुई (चार्ट 3ए और बी)।

केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 2024-25 की पहली छमाही में वर्ष दर वर्ष आधार पर 14.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण आयकर वसूली में 25.0 प्रतिशत की वृद्धि है, जबकि कॉरपोरेट कर संग्रह में 2.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 4ए)। 2023-24 की पहली छमाही में देखे गए पैटर्न के समान, 2024-25 की पहली छमाही में आयकर संग्रह कॉरपोरेट कर संग्रह से अधिक हो गया, जो अन्य बातों के साथ-साथ करदाताओं के अनुपालन में सुधार और कर आधार को व्यापक बनाने की दिशा में किए गए उपायों को दर्शाता है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष कर वसूली के भीतर, हाल के वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा में वृद्धि के साथ सुरक्षा लेनदेन कर से प्राप्तियां मजबूत रही हैं (बॉक्स ए)।

बॉक्स ए: सुरक्षा लेनदेन कर - भारतीय अनुभव

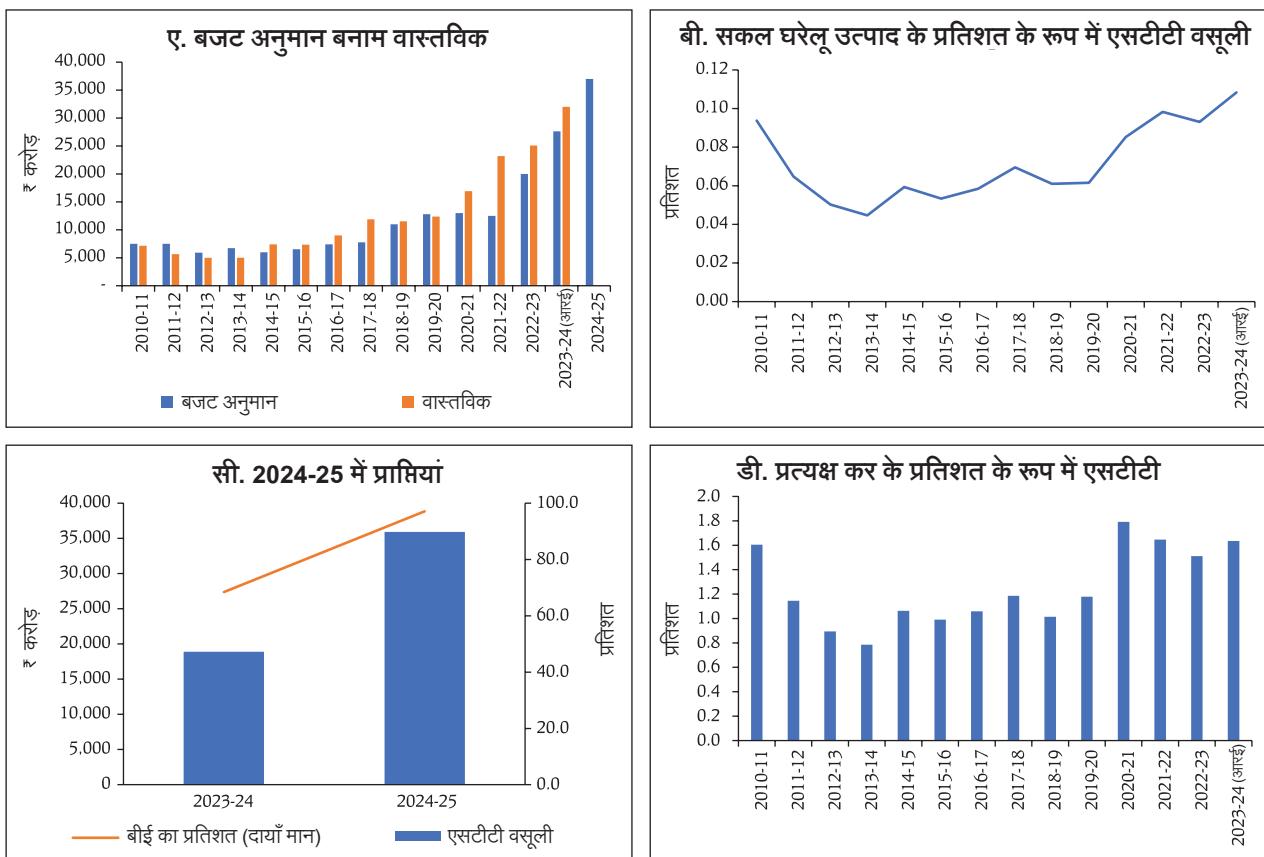
प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) स्टॉक एक्सचेंजों में प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। इसे भारत में 2004-05 के दौरान राजस्व सृजन को बढ़ाने, कर चोरी को खत्म करने, शेयर बाजार में सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर प्रदान करने और शोर मचाने वाले व्यापारियों/सड़ेबाजों को दूर भगाकर बाजार में अस्थिरता को कम करने के उद्देश्य से

पेश किया गया था। यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, इटली, तुर्की, दक्षिण कोरिया, भारत, इंडोनेशिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसी कई जी-20 अर्थव्यवस्थाओं ने अपने निवासियों द्वारा किए जाने वाले वित्तीय लेनदेन पर किसी न किसी तरह का कर लगाया है (मैथेसन, 2012)। दूसरी ओर, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं, जैसे पुर्तगाल, नीदरलैंड, स्वीडन, जापान, इटली और जर्मनी ने वित्तीय (जारी)

³ गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली तथा विविध पूँजी प्राप्तियां (अर्थात् विनिवेश एवं अन्य प्राप्तियां) शामिल हैं।

⁴ राज्यों की गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों में उनके द्वारा अधीनस्थ/अर्थ-सरकारी संस्थाओं को वितरित ऋणों और अग्रिमों की वसूली तथा अन्य विविध पूँजी प्राप्तियां शामिल होती हैं।

चार्ट ए.1: भारत में एसटीटी वसूली का रुझान



नोट: चार्ट ए.1सी में, 2024-25 और 2023-24 के लिए एसटीटी वसूली क्रमशः 10 नवंबर, 2024 और 10 नवंबर, 2023 तक के हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)।

लेनदेन करों को निरस्त कर दिया है, जो तकनीकी परिवर्तनों और उदारीकरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धी दबावों के कारण है, जिसने व्यापार को कम खर्चीले अन्य बाजारों में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है (हिलमैन और एशफोर्ड, 2012; बर्मन एट अल., 2016)। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय शेयर बाजार में ट्रेडिंग की मात्रा में वृद्धि के साथ-साथ तेजी से बढ़ते इकिवटी बाजार के कारण एसटीटी से राजस्व जुटाने में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में और निरपेक्ष रूप से वृद्धि देखी गई है (चार्ट ए.1 ए और बी)। 10 नवंबर, 2024 तक, एसटीटी वसूली ने 2024-25 के लिए अपने बजट अनुमान का 97 प्रतिशत प्राप्त करते हुए 90.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है (चार्ट ए.1सी)। महामारी के बाद की अवधि में केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह में एसटीटी की हिस्सेदारी बढ़ी है (चार्ट ए.1डी)।

राज्यों के स्वयं के प्रत्यक्ष कर संग्रह (जिसमें भूमि राजस्व और स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क से प्राप्तियां शामिल हैं) ने 2024-25 की पहली छमाही के दौरान 13.2 प्रतिशत (पहली

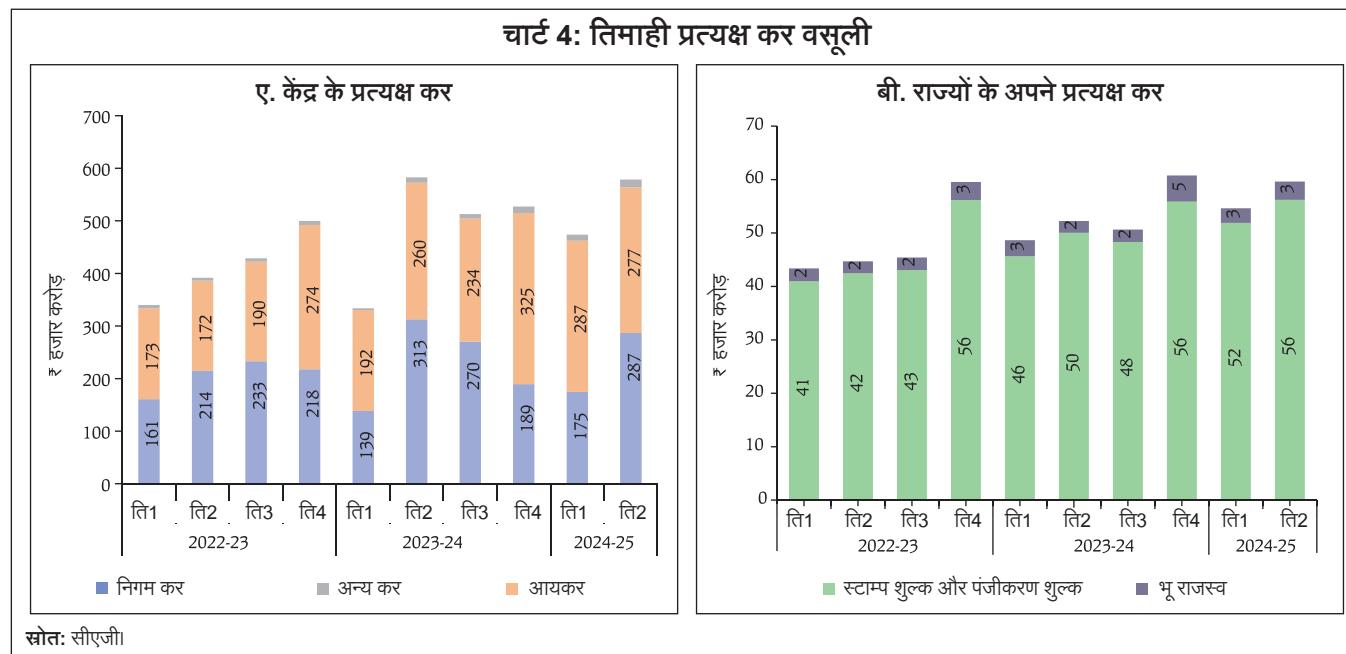
संदर्भ

Burman, L. E., Gale, W. G., Gault, S., Kim, B., Nunns, J. and Rosenthal, S. (2016). Financial Transaction Taxes in Theory and Practice. *National Tax Journal*, 69(1), 171-216, March.

Hillman, D. and Ashford, C. (2012). *Financial Transaction Tax: Myth-Busting*. Stamp Out Poverty, London, UK.

Matheson, T. (2012). Security Transaction Taxes: Issues and Evidence. *International Tax and Public Finance*, 19(6), 884-912.

तिमाही में 12.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 14.2 प्रतिशत) की वृद्धि के साथ अच्छा प्रदर्शन किया (चार्ट 4बी)।



केंद्र के अप्रत्यक्ष कर वसूली में 2024-25⁵ की पहली छमाही में 8.9 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें जीएसटी की प्रमुखता रही। 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान, अप्रत्यक्ष कर वसूली में 5.6 प्रतिशत (2023-24 की पहली तिमाही में 8.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसे जीएसटी वसूली में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि (2023-24 की पहली तिमाही में 11.5 प्रतिशत की वृद्धि) का समर्थन प्राप्त हुआ। दूसरी ओर, 2024-25 की पहली तिमाही में सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क वसूली में संकुचन देखा गया। 2024-25 की दूसरी तिमाही में, त्योहारी मांग से उत्साहित, जीएसटी वसूली में 11.8 प्रतिशत (एक साल पहले 6.0 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की गई। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रह में दूसरी तिमाही में क्रमशः 15.6 प्रतिशत और 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

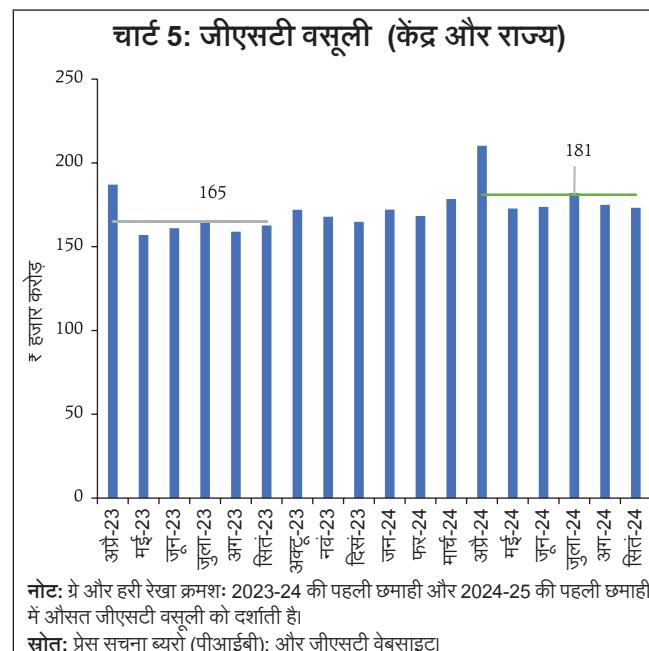
2024-25 की पहली छमाही में जीएसटी वसूली (केंद्र और राज्य) 10.9 लाख करोड़ रुपये रहा, जिसमें 9.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई (2023-24 की पहली छमाही में 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई), पहली और दूसरी तिमाही में औसत मासिक वसूली क्रमशः 1.86 लाख करोड़ रुपये और 1.77 लाख करोड़ रुपये रहा (चार्ट 5)।

राज्यों के मामले में, 2024-25 की पहली छमाही में कर राजस्व में वृद्धि को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) और केंद्र से कर हस्तान्तरण द्वारा समर्थित किया गया था। एसजीएसटी में मजबूत वृद्धि बढ़ती मांग, उच्च कर दरों और अधिक अनपालन

⁵ 2023-24 की पहली छमाही के दौरान, केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में 2022-23 की पहली छमाही की तलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

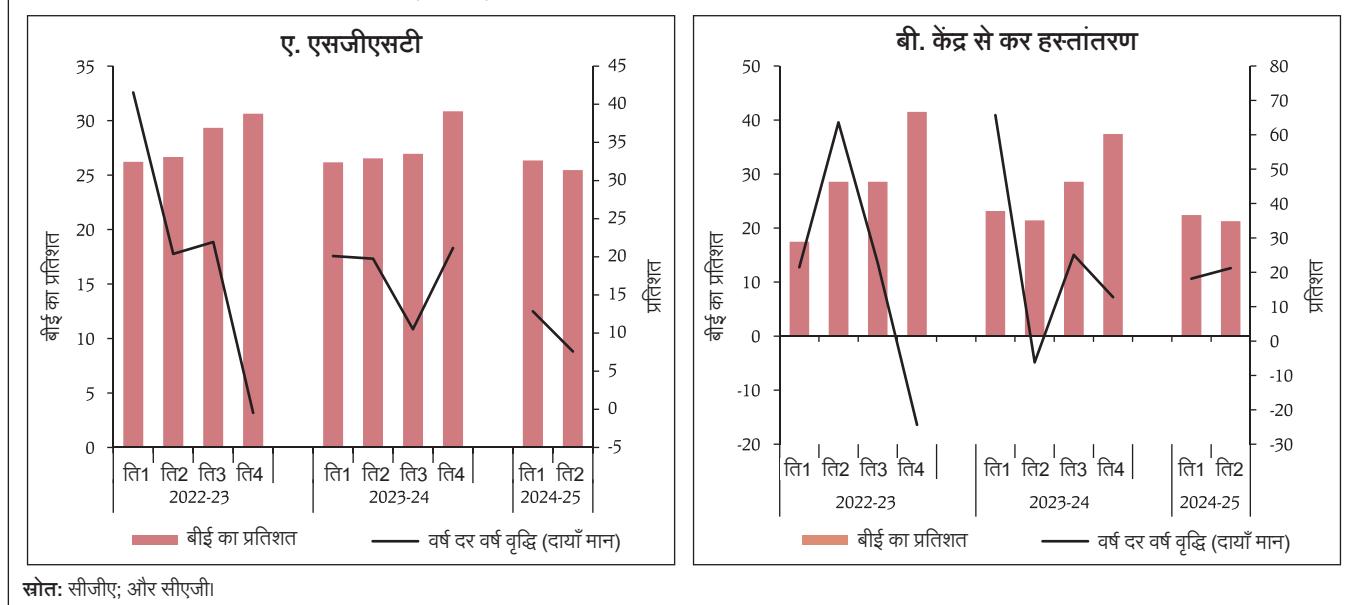
को दर्शाती है। 2024-25 की पहली छमाही में, राज्यों को आवंटन में पिछले वर्ष की इसी अवधि (चार्ट 6 ए और बी) की तुलना में 19.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

केंद्र के गैर-कर राजस्व में 2024-25 की दूसरी तिमाही में सालाना आधार पर 5.7 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, क्योंकि उच्च लाभांश और मुनाफे के साथ-साथ ब्याज प्राप्तियों की



⁶ वर्ष 2024-25 में 'लाभांश और लाभ' तथा 'ब्याज प्राप्तियों' से प्राप्त गैर-कर राजस्व, बजटीय गैर-कर राजस्व का क्रमशः 53.0 तथा 7.0 प्रतिशत होगा।

चार्ट 6: एसजीएसटी और केंद्र से कर हस्तांतरण का तिमाही प्रदर्शन

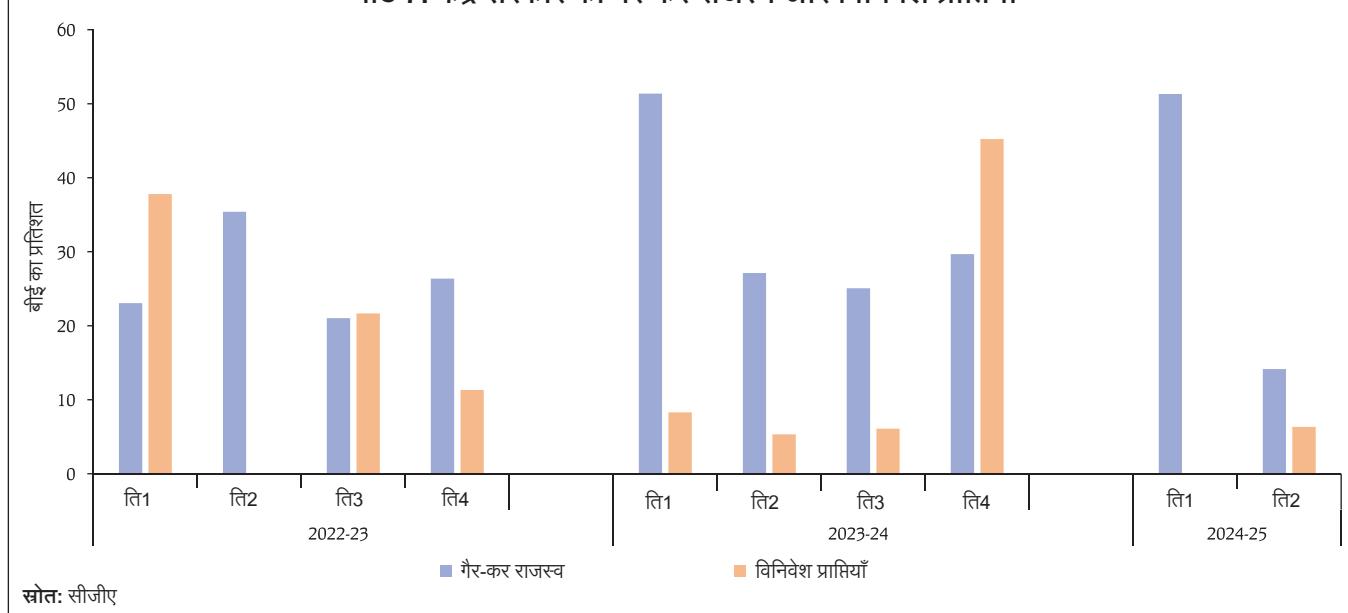


भरपाई आर्थिक सेवाओं से राजस्व में गिरावट से हुई।⁷ 2024-25 की पहली छमाही में विनिवेश प्राप्तियाँ धीमी रहीं और बजट राशि का 6.3 प्रतिशत जुटाया गया (2023-24 की पहली छमाही में 11.4 प्रतिशत) (चार्ट 7)।⁸

बी. व्यय

2024-25 (बजट अनुमान) में, केंद्र सरकार के कुल व्यय में 2023-24 (पीए) की तुलना में 8.5 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जिसमें राजस्व व्यय में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि और

चार्ट 7: केंद्र सरकार का गैर-कर राजस्व और विनिवेश प्राप्तियाँ



⁷ आर्थिक सेवाओं से प्राप्त गैर-कर राजस्व में कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ (कृषि फार्मों, वाणिज्यिक फसलों से प्राप्तियाँ, कृषि शिक्षा से शुल्क, कृषि उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण और ग्रेडिंग के लिए शुल्क आदि), सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय जल शक्ति अनुसंधान स्टेशन, पुणे आदि की प्राप्तियाँ), संचार (दूरसंचार ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के कारण प्राप्तियाँ शामिल हैं) आदि शामिल हैं। आर्थिक सेवाओं से प्राप्त गैर-कर राजस्व 2024-25 में बजटीय गैर-कर राजस्व का 33.4 प्रतिशत है।

⁸ 2024-25 की पहली छमाही के दौरान सरकार ने विनिवेश प्राप्तियाँ के रूप में 3,167 करोड़ रुपए जुटाए, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6,949 करोड़ रुपए जुटाए गए थे।

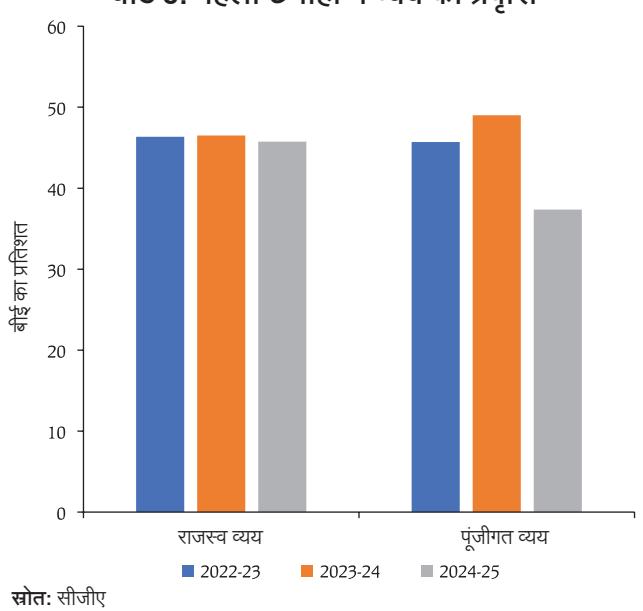
पूंजीगत व्यय में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है।⁹ 2024-25 की पहली छमाही में, बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय मोटे तौर पर पिछले वर्षों के रुझानों के अनुरूप रहा, जबकि पूंजीगत व्यय में कमी दर्ज की गई। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान प्राप्त बजटीय व्यय का अपेक्षाकृत कम हिस्सा, अन्य बातों के साथ-साथ, 2024-25 की पहली तिमाही में आम चुनावों के दौरान लागू आदर्श आचार संहिता के कारण है (चार्ट 8)।

शीर्ष 6 मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय,¹⁰ जिसमें 2024-25 के लिए कुल बजटीय पूंजीगत व्यय का 95 प्रतिशत शामिल है, 2024-25 की पहली छमाही के दौरान बजट अनुमान का 37.3 प्रतिशत गिर गया (2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 51.8 प्रतिशत की तुलना में) (चार्ट 9)। इसी तरह, 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत व्यय 2024-25 की पहली छमाही के दौरान ₹30,040 करोड़ हो गया (2023-24 की पहली छमाही के दौरान ₹53,541 करोड़ की तुलना में)।¹¹ सितंबर 2024 में, वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारत सरकार

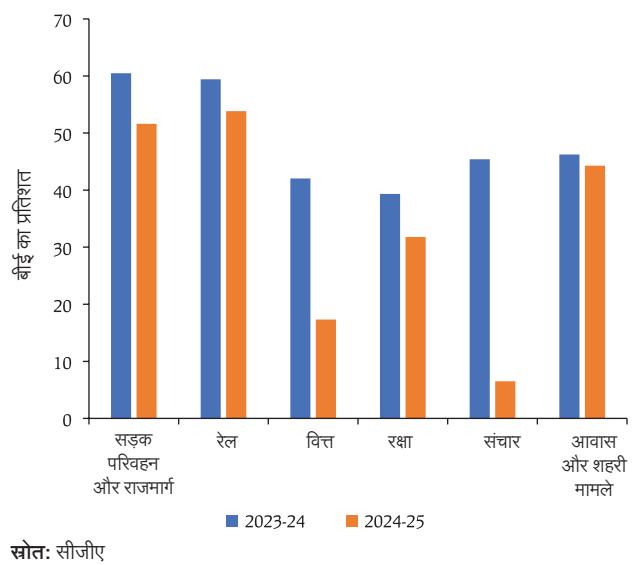
(जीओआई) ने नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों को आसान बना दिया, जिससे 2024-25 की दूसरी छमाही में पूंजीगत व्यय सहित सार्वजनिक खर्च को बढ़ावा मिलना चाहिए।¹² इसके अलावा, केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों का पहला बैच भी प्रस्तावित किया था, जिसमें 44,143 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय शामिल है (चार्ट 10)।

ईंधन और उर्वरकों सहित प्रमुख सब्सिडी पर केंद्र सरकार का व्यय, 2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 56.3 प्रतिशत रह गया, जो 2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 55.1 प्रतिशत था, जिसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कीमतों में गिरावट (2024-25 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 58.2 प्रतिशत जबकि 2023-24 की पहली छमाही में बजट अनुमान का 95.9 प्रतिशत) के कारण पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर कम वार्षिक व्यय है। 2024-25 की पहली छमाही में प्रमुख सब्सिडी पर कुल व्यय में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी का हिस्सा क्रमशः 56.6 प्रतिशत और 41.7 प्रतिशत था, जबकि

चार्ट 8: पहली छमाही में व्यय की प्रवृत्ति



चार्ट 9: पहली छमाही में प्रमुख मंत्रालयों का पूंजीगत व्यय

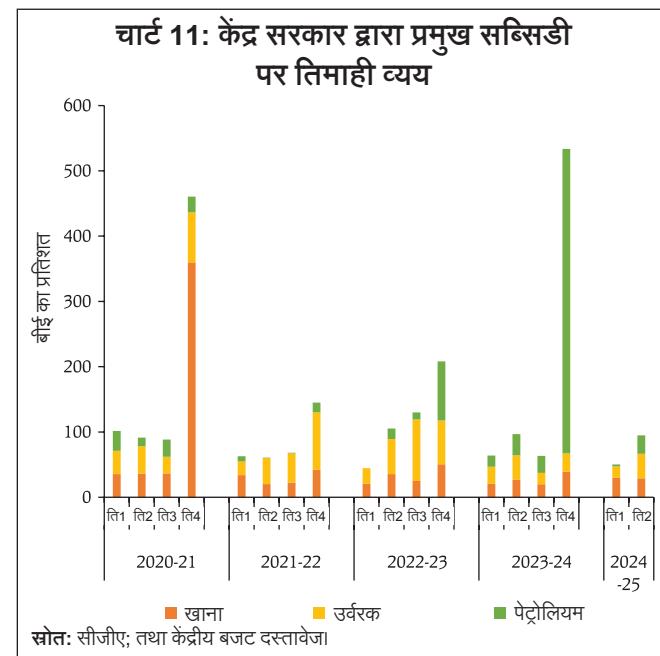
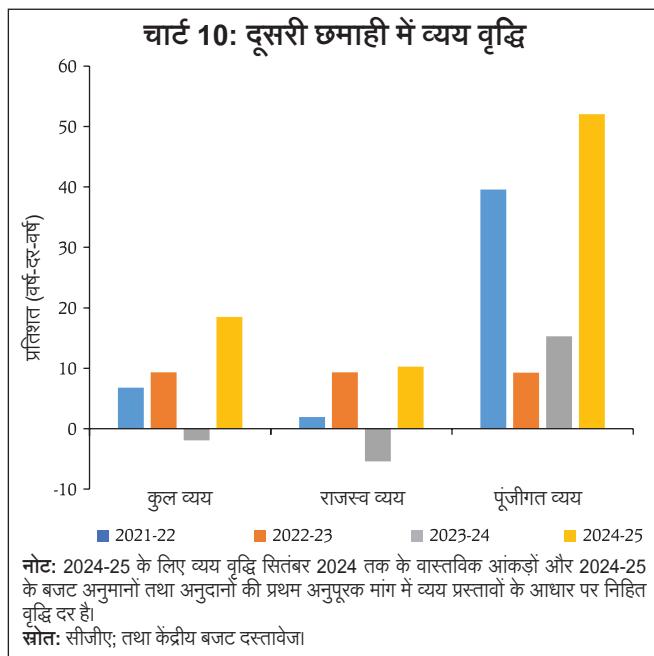


⁹ पूंजीगत परिव्यय (अर्थात् क्रण और अग्रिम को छोड़कर पूंजीगत व्यय) में 2024-25 में 16.7 प्रतिशत की वृद्धि का बजट रखा गया है, जबकि 2023-24 (पीए) में 26.0 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

¹⁰ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, संचार मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय।

¹¹ मासिक सारांश रिपोर्ट, व्यय विभाग।

¹² आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) द्वारा 4 सितंबर, 2024 को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, बजट को क्रियान्वित करने के लिए परिचालनगत लंबीलापन प्रदान करने के लिए बड़ी निर्माण (₹500 करोड़ या उससे अधिक) से संबंधित शर्तों में अगली सूचना तक ढील दी जाएगी। नई प्रदान की गई छूट एकल नोडल एजेंसी (एसएनए) / केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) और मासिक व्यय योजना (एमईपी) / तिमाही व्यय योजना (क्यूईपी) के अनुपालन दिशानिर्देशों के अधीन रहेगी।



पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह क्रमशः 46.1 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत था (चार्ट 11)।

भारत महिला विकास से महिला नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है।¹³ महिलाओं के कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं के लिए केंद्र का व्यय 2015-

16 में ₹81,249 करोड़ से बढ़कर 2024-25 (बजट अनुमान) में ₹3,27,158 करोड़ हो गया है। कुल केंद्रीय बजट में लिंग बजट का हिस्सा 2024-25 (बजट अनुमान) में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गया है, जो 2005-06 में लिंग बजट विवरण (जीबीएस) की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है (बॉक्स बी)।

बॉक्स बी: भारत में लैंगिक बजटिंग के बीस वर्ष

लैंगिक बजटिंग लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और लड़कियों एवं महिलाओं के विकास का समर्थन करने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करता है (आईएमएफ, 2016)। यह बजटीय प्रथाओं की लिंग प्रतिक्रियाशीलता का विवरण देकर नीति निर्माण में सहायता करता है। लैंगिक बजट लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रयासों को दर्शाते हैं - एक मान्यता प्राप्त सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)। ऑस्ट्री एवं अन्य (2018) ने अनुमान लगाया कि महिला श्रम बल भागीदारी में बाधाओं को दूर करने से महत्वपूर्ण उत्पादन और कल्याण लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

1984 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसकी शुरुआत के बाद से, लैंगिक बजट को 100 से अधिक देशों (यूएन महिला, 2023) द्वारा अपनाया गया है, जो मूल, राजकोषीय नीति घटकों, कानूनी प्रावधानों, शामिल सरकारों के स्तर और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका में विभिन्न प्रथाओं को प्रदर्शित करता है (स्टॉट्स्की, 2016)।

1995 में इसे अपनाने वाला एक प्रारंभिक देश दक्षिण अफ्रीका ने 2019 में लैंगिक उत्तरदायी योजना, बजट, निगरानी, मूल्यांकन और लेखा परीक्षा रूपरेखा (जीआरपीबीएमईएफ) की स्थापना की, जो लैंगिक समानता प्रतिबद्धताओं के लिए व्यापक संस्थागत उत्तरदायित्व के लिए एक कानूनी आधार प्रदान करता है और सरकार के सभी स्तरों पर लैंगिक उत्तरदायी नीति को बढ़ावा देता है। ब्राजील में, नागरिक समाज ने लैंगिक संवेदनशील बजट के प्रति सरकारी जवाबदेही बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है (रेस, 2006)। चीन में, कुछ स्थानीय सरकारों ने सार्वजनिक वित्त प्रबंधन उपाय के रूप में लैंगिक बजट को शामिल करने की पहल की है (अलोंसो एवं अन्य., 2021)। बेल्जियम ने कानूनी तौर पर मंत्रालयों को लिंग-विभाजित डेटा बनाए रखने और प्रगति को ट्रैक करने के लिए लिंग संकेतक विकसित करने का आदेश दिया है। फिनलैंड पूर्वनिमान-विशेषण पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके तहत मंत्रालयों को बजट प्रस्तावों के अपेक्षित लिंग प्रभाव की (जारी)

¹³ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24।

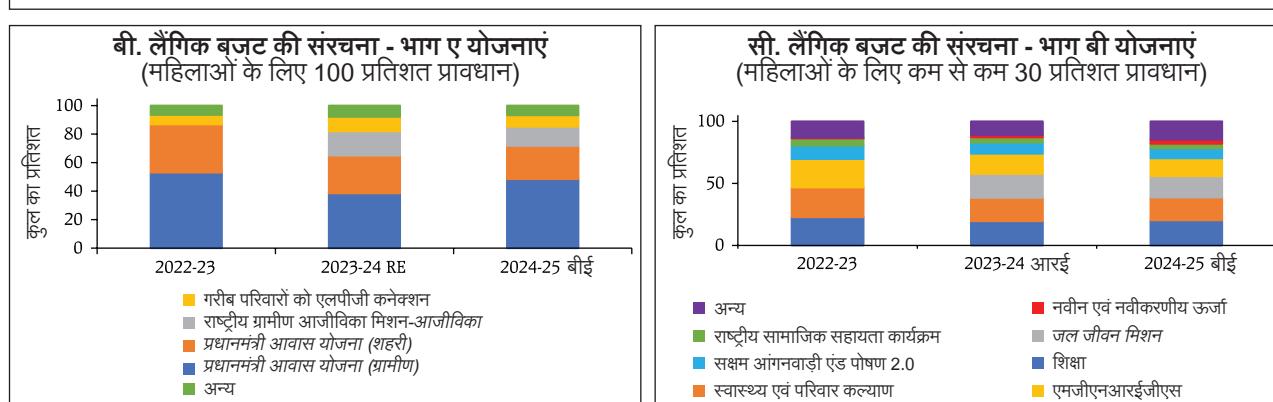
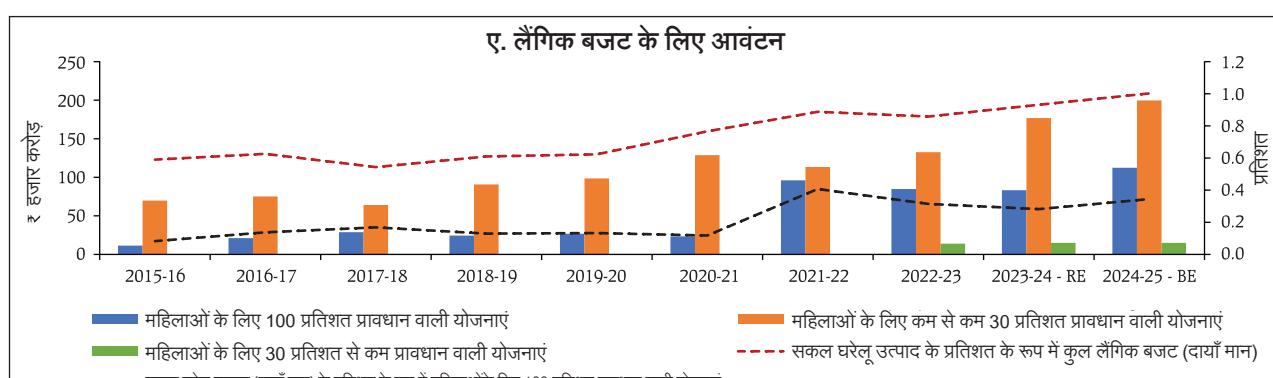
रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है (एलोमाकी और यलोस्टालो, 2021)। भारत ने अपना पहला जीबीएस केंद्रीय बजट 2005-06 में पेश किया और लिंग-संवेदनशील प्रथाओं को बढ़ावा देने और रिपोर्ट करने के लिए 2007 में मंत्रालयों में लैंगिक बजटिंग सेल की स्थापना की। ओडिशा 2004-05 में लैंगिक बजटिंग को अपनाने वाला पहला राज्य था।¹⁴ 2024-25 के दौरान, 11 राज्यों ने जीबीएस प्रस्तुत किए।

केंद्र के लैंगिक बजट को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है: भाग ए में महिलाओं के कल्याण के लिए 100 प्रतिशत आवंटन वाली योजनाएं शामिल हैं; भाग बी में ऐसी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत आवंटन महिलाओं के कल्याण के लिए निर्देशित हैं; और भाग सी, जिसे 2024-25 में पेश किया गया है, में महिलाओं के कल्याण के लिए 30 प्रतिशत से कम आवंटन वाली योजनाएं शामिल हैं। कुल व्यय में लैंगिक बजट का हिस्सा

2014-15 में 4.5 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 (बीई) में 6.8 प्रतिशत हो गया, जिसमें भाग ए की योजनाएं तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही हैं। 2021-25 के दौरान भाग ए के तहत औसत व्यय में तेज वृद्धि मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना और गरीब परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन के लिए बढ़े हुए आवंटन से प्रेरित है। 2024-25 (बजट अनुमान) के लिए, लैंगिक बजट के लिए 3.27 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2023-24 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 18.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट बी.1ए)।

2022-23 से 2024-25 के बीच, भाग ए मुख्य रूप से आवास, स्वरोजगार को बढ़ावा देने और घरों में स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन उपलब्ध कराने पर केंद्रित था। भाग ए में 19 मंत्रालयों में से शीर्ष तीन - ग्रामीण विकास (63.7 प्रतिशत); आवास और शहरी मामले (23.3 प्रतिशत); और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (8.1

चार्ट बी.1: केंद्रीय लैंगिक बजट - रुझान और संरचना



टिप्पणियाँ: 1. शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा कुल व्यय को दर्शाता है।
2. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में आरसीएच और स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए लचीले पूल पर व्यय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य भिशन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किए गए अन्य महिला-उन्मुख व्यय शामिल हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़।

(Contd.)

¹⁴ सूचना बुलेटिन, अनुसंधान एवं सूचना प्रभाग, लोक सभा सचिवालय, 2016।

प्रतिशत) - 2024-25 (बीई) में बजटीय व्यय का 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हैं। भाग बी में लगभग 27 मंत्रालयों के अधिक बिखरे हुए व्यय हैं, जो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी व्यय, स्वच्छ पेयजल के प्रावधान और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका सुरक्षा पर केंद्रित हैं (चार्ट बी.1बी और सी)। 2024-25 में प्रस्तुत भाग सी में चालू वित्त वर्ष के लिए ₹15,000 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) शामिल है। लैंगिक बजटिंग ने भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए राजकोषीय नीतियों में बदलाव को प्रेरित किया है, जिससे भारत में लिंग-उन्मुख लक्षणों को आगे बढ़ाया जा रहा है (स्टॉट्स्की, 2016)। एक वैश्विक सर्वेक्षण ने भारत को 23 देशों में से एक के रूप में पहचाना है, जिसमें प्रमुख लैंगिक बजटिंग प्रयास हैं (स्टॉट्स्की, 2016)। व्यय को वर्गीकृत करने के लिए स्पष्ट तंत्र और लैंगिक बजट के अंतर्गत भारिता निर्दिष्ट करने के लिए पारदर्शी मानदंड स्थापित करने से पारदर्शिता को और बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, 2022 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित लैंगिक बजटिंग अधिनियम जैसा कानूनी प्रावधान बनाना, इन प्रयासों को निर्देशित करने के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान कर सकता है।

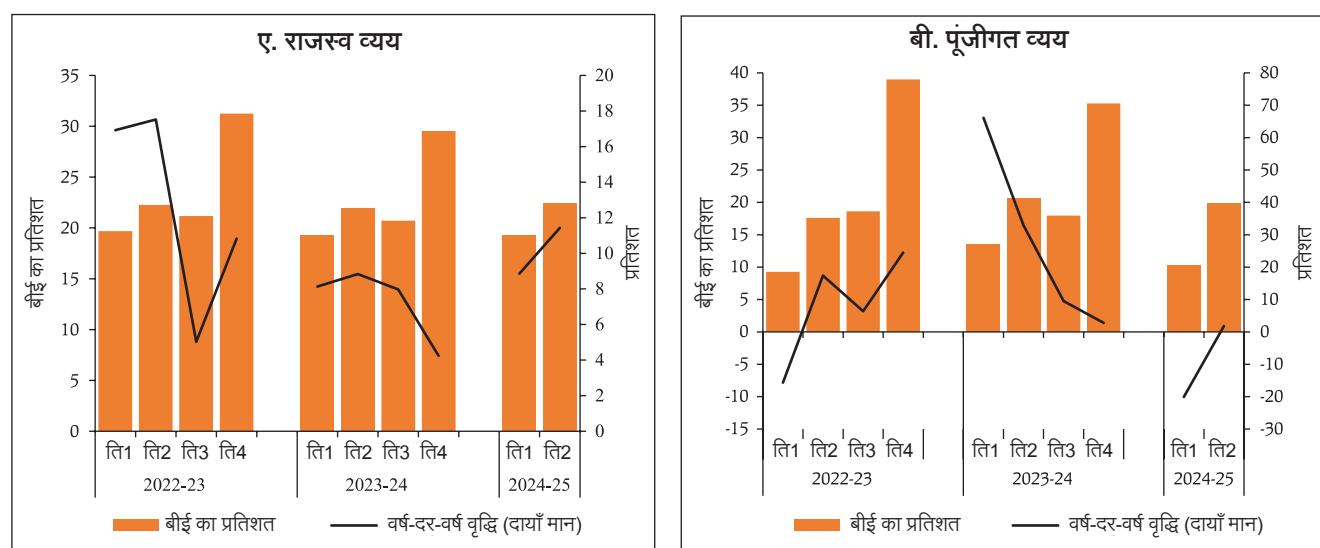
संदर्भ

- Elomaki, A. and Ylostalo, H. (2021). Gender Budgeting in the Crossroad of Gender Policy and Public Financial Management: The Finnish case. *Public Money and Management*.
- Alonso, V. A., Currinstine, T. R., Preston, G., Soler, A., Tchelishvili, N., Weerathunga, S. (2021). Gender Budgeting in G20 Countries. *IMF Working Papers*, 2021/269, International Monetary Fund.
- Stotsky, J. G. (2016). Gender Budgeting: Fiscal Context and Current Outcomes. *IMF Working Paper*, No. 16/149, July.
- Explainer: What is Gender Responsive Budgeting? (November 2023). UN Women.
- Ostry, J., Alvarez, J., Espinoza, R. and Papageorgiou, C. (2018). Economic Gains from Gender Inclusion: New Mechanisms, New Evidence. Staff Discussion Notes.
- Raes, F. (2006). What Can We Expect from Gender Sensitive Budgets? Strategies in Brazil and Chile in a Comparative Perspective', Network Women in Development Europe – WIDE.

2024-25 की पहली और दूसरी तिमाही में राज्यों के राजस्व व्यय में क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2023-24 की इसी तिमाहियों में दर्ज की गई वृद्धि से अधिक थी। राज्यों ने 2024-25 की पहली तिमाही में अपने

बजटीय राजस्व व्यय का 41.6 प्रतिशत (छ1:2023-24 में 41.3 प्रतिशत) खर्च किया। दूसरी ओर, 2024-25 की पहली तिमाही में उनके पूंजीगत व्यय में 6.9 प्रतिशत की कमी आई, जिसमें 2024-25 की पहली तिमाही में 20.1 प्रतिशत की गिरावट और

चार्ट 12: राज्य सरकारों का त्रैमासिक व्यय



स्रोत: सीएजी; तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

2024-25 की दूसरी तिमाही में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 12ए और बी)। परिणामों पर अधिक ध्यान देने से व्यय दक्षता में

वृद्धि हो सकती है (बॉक्स सी)।

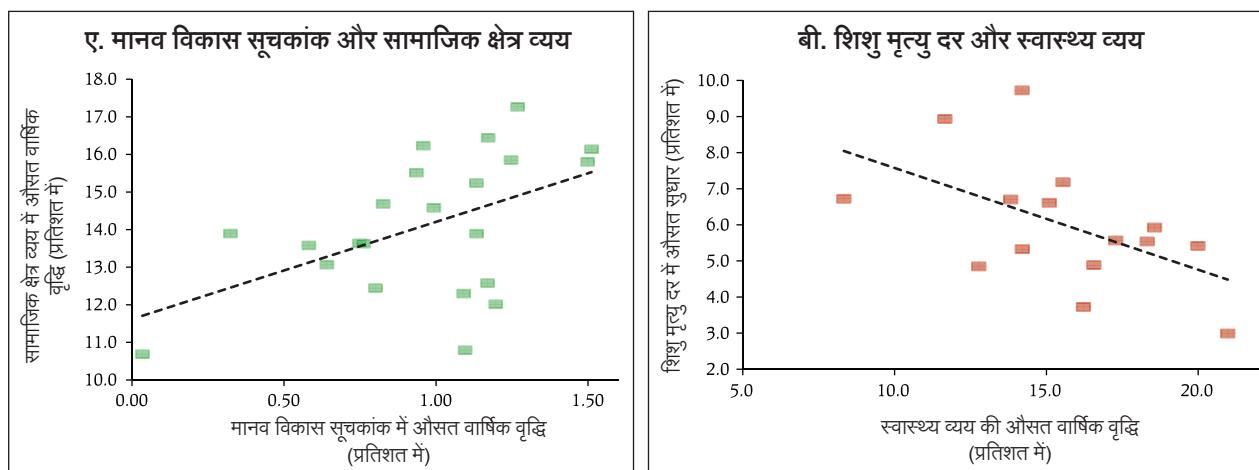
बॉक्स सी: व्यय प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए परिणाम बजट

भारतीय राज्यों द्वारा सामाजिक क्षेत्र पर व्यय 2005-06 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 (बीई) में 8.1 प्रतिशत हो गया है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं की प्राथमिकता बढ़ रही है। हालांकि, इस खर्च की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि यह कितनी अच्छी तरह से ठोस परिणामों में तबदील होती है। सार्वजनिक संसाधनों से 'ऐसे का मूल्य' सुनिश्चित करना किसी भी अर्थव्यवस्था के सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है (जेना, 2013)। नीति आयोग और चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोगों ने संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने के लिए प्रदर्शन से जुड़े बजट की वकालत की (कुंडू, 2024)। सामाजिक क्षेत्र के व्यय की लागत-प्रभावशीलता में अंतर-राज्यीय भिन्नता परिणामों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करती है। उदाहरण के लिए एचडीआई सुधार के संदर्भ में सामाजिक क्षेत्र के खर्च पर सीमांत प्रतिलाभ में काफी भिन्नता है, जो 0.003 प्रतिशत से लेकर 0.102 प्रतिशत (सामाजिक क्षेत्र के खर्च में प्रतिशत वृद्धि के लिए एचडीआई सूचकांक में प्रतिशत सुधार) तक है [चार्ट सी.1ए]। इसी तरह, स्वास्थ्य पर बढ़ा हुआ खर्च समान रूप से बेहतर नतीजों में तबदील नहीं होता है। उदाहरण

के लिए, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) में कमी स्वास्थ्य क्षेत्र के खर्च पर सीमांत प्रतिलाभ में महत्वपूर्ण अंतर-राज्यीय असमानताओं को दर्शाती है (चार्ट सी.1बी)। ये भिन्नताएं बजटीय परिव्यय से आगे बढ़कर परिणाम-उन्मुख सार्वजनिक खर्च पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं।

आउटकम बजटिंग (ओबी) सार्वजनिक व्यय को मापने योग्य विकासात्मक आउटपुट और परिणामों से जोड़कर इस चुनौती का समाधान करता है। इनपुट पर ध्यान केंद्रित करने वाले पारंपरिक बजटों के विपरीत, ओबी परिणामों पर जोर देता है, अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और विकासात्मक प्राथमिकताओं के साथ संरेखण को बढ़ावा देता है। 2005 में संघ स्तर पर पेश किए गए, ओबी को तब से 11 राज्यों (सीबीजीए, 2021) द्वारा अपनाया गया है। नीति आयोग के एक संलग्न कार्यालय विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ) ने एक आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क विकसित किया है और कई राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के परिणाम-आधारित बजट बनाए हैं। परिणाम बजट का कार्यान्वयन और ढांचा राज्यों में अलग-अलग है। हालांकि,

चार्ट सी.1: परिणाम संकेतक बनाम राज्यों द्वारा व्यय



- टिप्पणियाँ:**
- जो राज्य 0.6 एचडीआई मूल्य से ऊपर हैं तथा औसत आईएमआर से ऊपर हैं, उन्हें विश्लेषण से बाहर रखा गया है, क्योंकि उनका आधार ऊंचा है।
 - मानव विकास सूचकांक और सामाजिक क्षेत्र व्यय के लिए 15 वर्ष की अवधि (2005-06 से 2021-22) में औसत की गणना की जाती है।
 - शिशु मृत्यु दर और स्वास्थ्य व्यय के लिए औसत की गणना 10 वर्ष की अवधि (2010-11 से 2020-21) में की गई है।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जारी)

चुनौतियाँ बनी हुई हैं, जिनमें क्षमता निर्माण, बढ़ी हुई पारदर्शिता और बेहतर निगरानी तंत्र की आवश्यकता शामिल है।

सभी राज्यों और क्षेत्रों में ओबी को बढ़ाना, इसके ढांचे को एसडीजी बैंचमार्क के साथ संरेखित करना और मजबूत डेटा सिस्टम में निवेश करना व्यय दक्षता को संस्थागत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर पर क्षमता निर्माण और राज्यों के बीच सहयोगात्मक ज्ञान साझाकरण ओबी के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। सभी राज्यों में ओबी को संस्थागत बनाने से सतत विकास की उपलब्धि और सार्वजनिक व्यय के प्रभाव को अधिकतम करने में मदद मिल सकती है।

संदर्भ

Kundu, P. (2024). Issues and Trends in Public Expenditure. *Economic and Political Weekly*, Volume 59, Issue No. 33. August 17, 2024.

Rawal, S and Gupta, M. (2024). Need for SDG-linked outcome budgeting in India: A case of Assam. *Down to Earth*, February 21, 2024.

Jena, P.R. (2013) Improving Public Financial Management in India: Opportunities to Move Forward, *NIPFP Working Paper No 2013-123*, April.

CBGA (2021). Outcome Budgeting in India: The Efforts being made at the Union and State Levels. Centre for Budget and Governance Accountability (CBGA).

III. राजकोषीय घाटा और उसका वित्तपोषण

केंद्र सरकार

ए. राजकोषीय घाटा

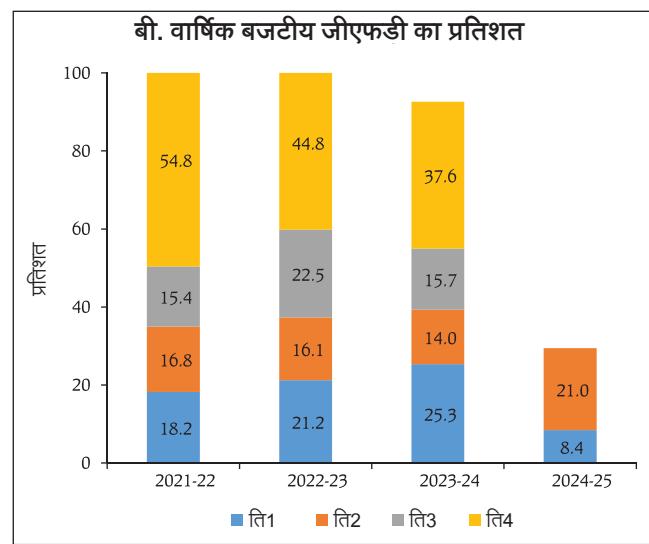
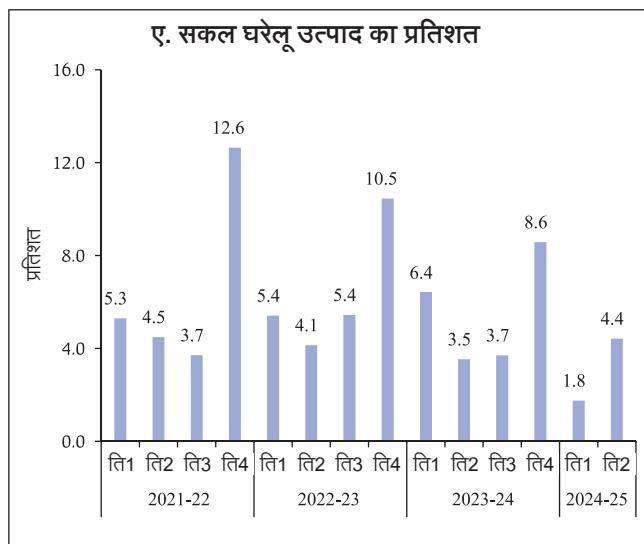
केंद्र सरकार ने 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के जीएफडी का बजट रखा है, जबकि 2023-24 (पीए) में यह 5.6 प्रतिशत था, जो 2025-26 तक सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 प्रतिशत से कम के मध्यम अवधि के जीएफडी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ग्लाइड पथ के अनुरूप है। 2024-25 की पहली छमाही के दौरान, केंद्र सरकार का जीएफडी बजट अनुमान का 29.4 प्रतिशत रहा, जो 2023-24 की इसी अवधि के दौरान

39.3 प्रतिशत से कम था, और यह अनुपात एक दशक में अपने सबसे निचले स्तर पर था (चार्ट 13ए और बी)। 2024-25 की पहली छमाही में राजस्व घाटे और प्राथमिक घाटे में भी इसी तरह की कमी देखी गई।

बी. जीएफडी का वित्तपोषण

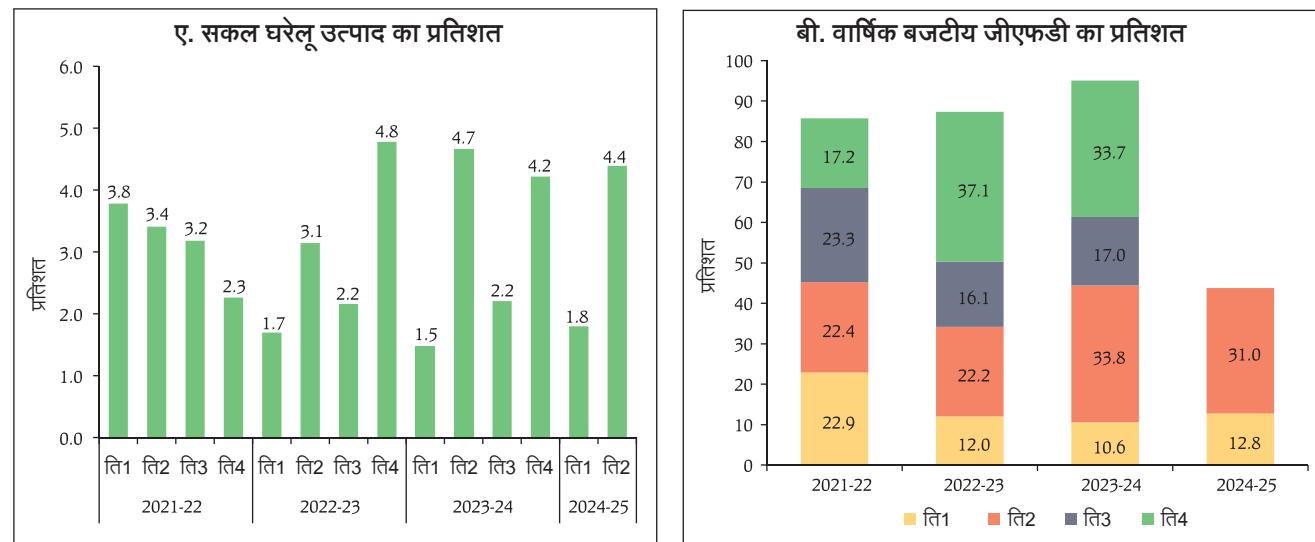
2024-25 की पहली छमाही में केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए बजट में निर्धारित बाजार उधारी का 52.8 प्रतिशत पूरा कर लिया, जिससे वर्ष की पहली छमाही के दौरान उसके जीएफडी के बड़े हिस्से का वित्तपोषण हुआ। सरकार ने 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए अपने उधारी लक्ष्य पर कायम रहने का फैसला किया है।

चार्ट 13: केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा



स्रोत: सीजीए; तथा केंद्रीय बजट दस्तावेज।

चार्ट 14: राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा



स्रोत: सीएजी; तथा राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़।

राज्य सरकार

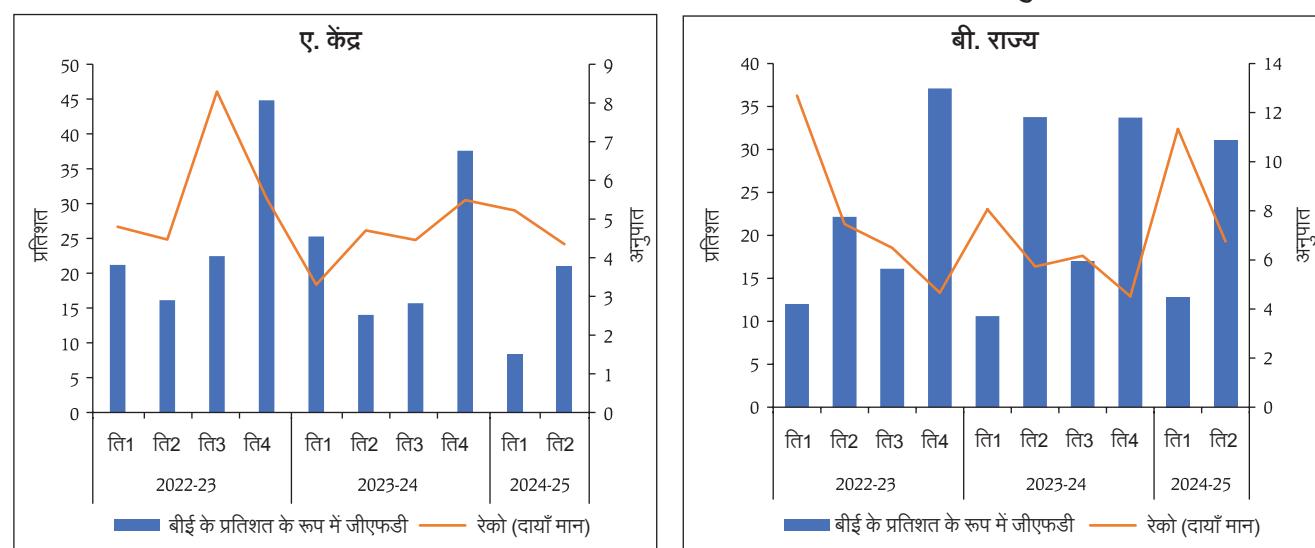
ए. राजकोषीय घाटा

राज्यों ने 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 3.2 प्रतिशत के समेकित जीएफडी का बजट बनाया था, जबकि 2023-24 (पीए) में यह 2.9 प्रतिशत था। 2024-25 के दौरान, राज्यों ने पिछले वर्ष की तुलना में पहली तिमाही और दूसरी तिमाही में अपने बजटीय जीएफडी का कम अनुपात खर्च किया है। तदनुसार, 2024-25 के उत्तरार्ध में राज्यों के लिए उपलब्ध

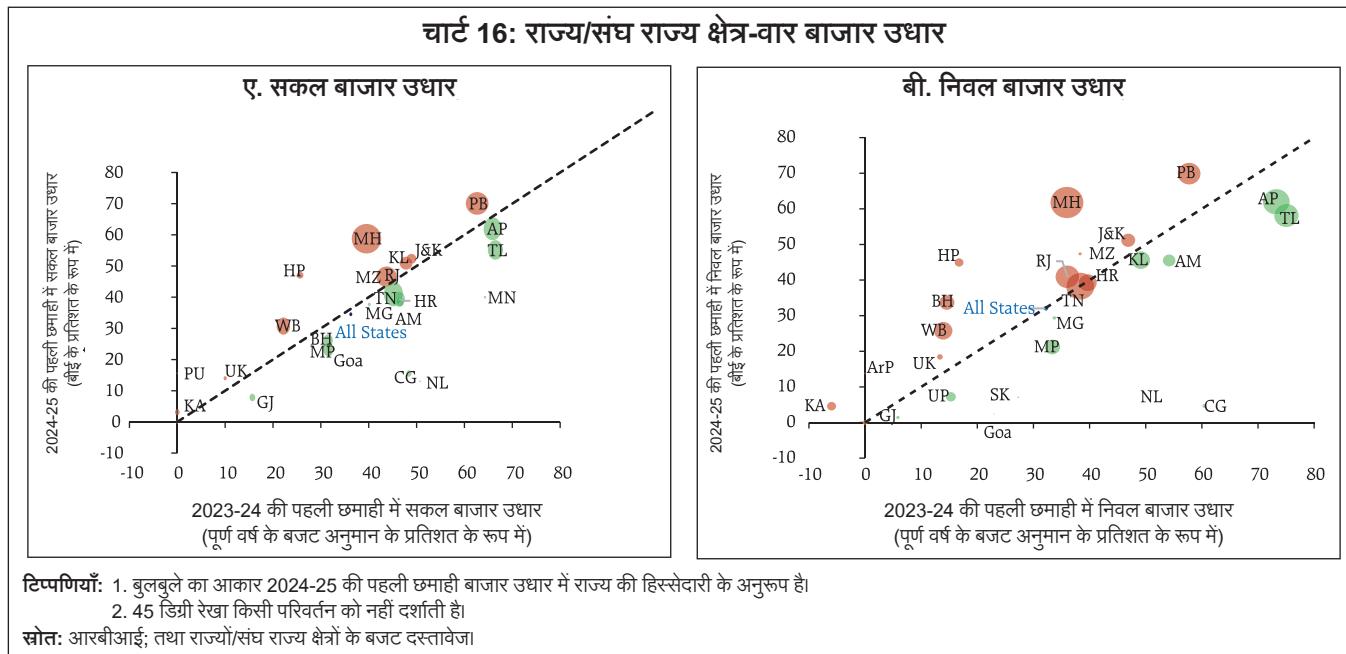
राजकोषीय स्थान उनके बजटीय जीएफडी का 56.1 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 55.6 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट 14ए और बी।)

पूंजीगत व्यय में कमी को देखते हुए केंद्र का राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय (आरईसीओ) अनुपात एक साल पहले के 3.9 से बढ़कर 2024-25 की पहली छमाही में 4.7 हो गया। इसी अवधि के दौरान, राज्यों का अनुपात भी 6.6 से बढ़कर 8.3 हो गया (चार्ट 15ए और बी।)

चार्ट 15: केंद्र और राज्यों के लिए सकल राजकोषीय घाटा और व्यय की गुणवत्ता



स्रोत: सीजीए; सीएजी; तथा केंद्र और राज्यों के बजट दस्तावेज़।



बी. जीएफडी का वित्तपोषण

2024-25 की पहली छमाही के दौरान राज्यों द्वारा शुद्ध बाजार उधारी में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान, राज्यों ने अपने बजटीय निवल बाजार उधारी का 32.1 प्रतिशत (2023-24 की इसी अवधि में 32.2 प्रतिशत) उपयोग किया। तेरह राज्यों ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अपने बजटीय निवल उधारी का उच्च अनुपात उपयोग किया। सकल बाजार उधारी में पिछले वर्ष की तुलना में 7.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो बजटीय राशि का 34.5 प्रतिशत है (चार्ट 16ए और बी)।

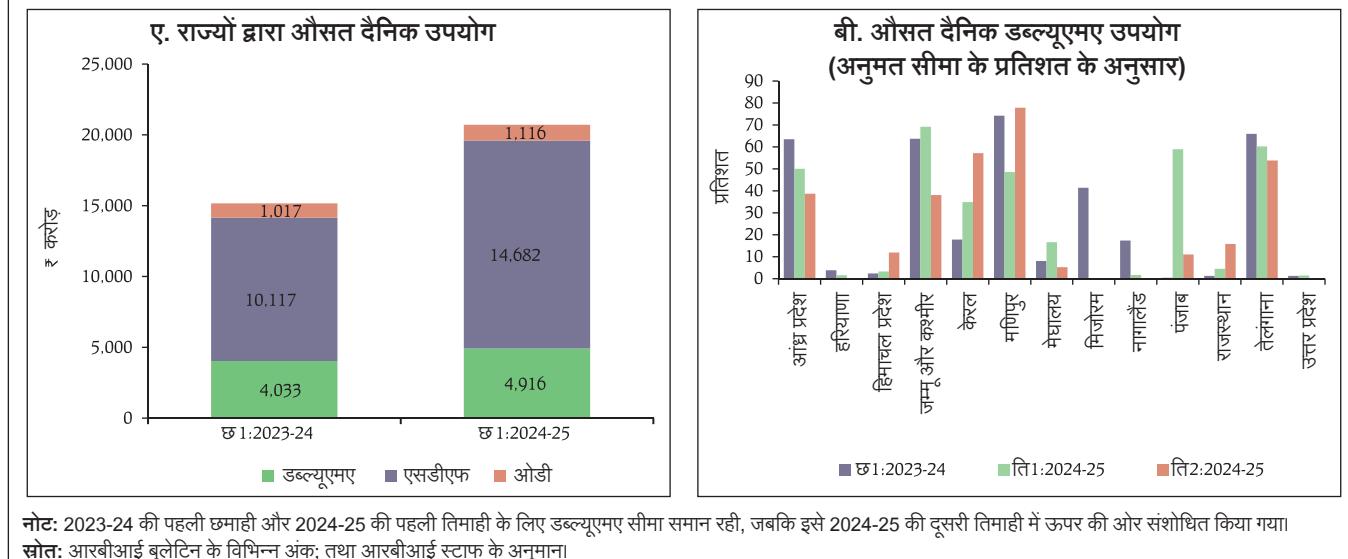
रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधा में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 2024-25 की पहली छमाही में 36.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1 जुलाई, 2024 से अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा को संशोधित किया गया। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल डब्ल्यूएमए सीमा अब ₹60,118 करोड़ है, जो कि पहले की सीमा

₹47,010 करोड़ से 27.9 प्रतिशत अधिक है। परिणामस्वरूप, राज्यों ने 2024-25 की पहली तिमाही में स्वीकार्य डब्ल्यूएमए सीमा का 9.6 प्रतिशत और दूसरी तिमाही में 8.8 प्रतिशत उपयोग किया। डब्ल्यूएमए और विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के अंतर्गत राज्यों द्वारा औसत उपयोग में क्रमशः 21.9 प्रतिशत और 45.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा के अंतर्गत उपयोग में 2024-25 की पहली छमाही में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 17ए और बी)।

IV. सामान्य सरकारी वित्त

सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य संयुक्त) के लिए जीएफडी को 2023-24 (संशोधित अनुमान) में जीडीपी के 9.0 प्रतिशत से कम करके 2024-25 (बीई) में जीडीपी के 7.6 प्रतिशत पर बजट में रखा गया है। 2024-25 की पहली तिमाही में जीएफडी-जीडीपी अनुपात केंद्र और राज्यों के कुल व्यय में धीमी वृद्धि और मजबूत कर संग्रह के कारण कम था। 2024-25 की दूसरी तिमाही में केंद्र और राज्यों के व्यय में वृद्धि के साथ ही जीएफडी-

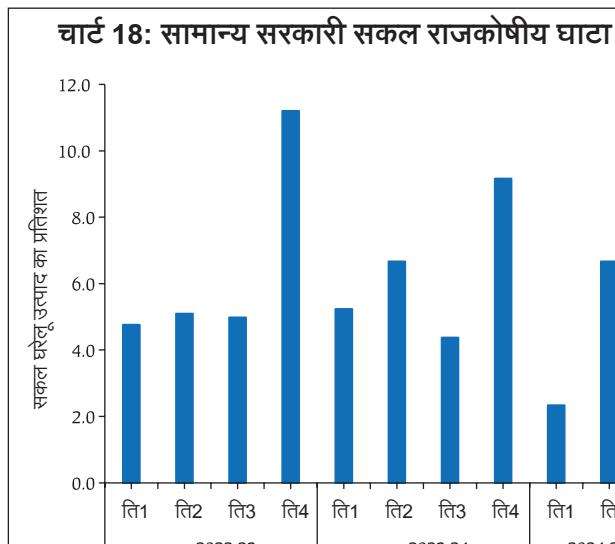
चार्ट 17: रिजर्व बैंक से उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता



जीडीपी अनुपात अपने पिछले रुझानों के अनुरूप बढ़ गया (चार्ट 18)।

V. निष्कर्ष

केंद्र ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के कर संग्रह में वृद्धि दर्ज की है और उम्मीद है कि यह उछाल जारी रहेगा। रिजर्व बैंक द्वारा बड़े अधिशेष हस्तांतरण से केंद्र के गैर-कर राजस्व में वृद्धि हुई है। आम चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के प्रभाव को दर्शाते हुए, केंद्र और राज्य दोनों के सरकारी खर्च में 2024-25 की पहली छमाही में कमी आई है और 2024-25 की दूसरी छमाही में इसमें तेजी आने की उम्मीद है। कुल मिलाकर, केंद्र ने 2024-25 की पहली छमाही में अपने बजटीय राजस्व का आधे से अधिक हासिल कर लिया है, जबकि अपने व्यय को पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित व्यय के आधे से भी कम पर सीमित रखा है। यह केंद्र के लिए 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.9 प्रतिशत के अपने जीएफडी लक्ष्य को पूरा करने के लिए अच्छा संकेत है। कई राज्यों ने अपने 2024-25 के बजट में कृषि और घरों को मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, बेरोजगार युवाओं को भत्ते और महिलाओं को मौद्रिक सहायता सहित रियायतों की घोषणा की है। इस तरह के खर्च से संसाधन महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास से दूर हो सकते हैं।



परिशिष्ट सारणी

सारणी I: अप्रैल-सितंबर के दौरान केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति

वर्षतु	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक आंकड़े		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	1622.4	1397.1	3129.2	2632.3	51.8	53.1	16.1	19.5
1.1. निवल कर राजस्व	1265.2	1160.3	2583.5	2330.6	49.0	49.8	9.0	14.7
1.2. गैर-कर राजस्व	357.2	236.8	545.7	301.7	65.5	78.5	50.9	50.2
1.3. ब्याज प्राप्तियां	20.4	17.3	38.2	24.8	53.3	69.7	17.6	38.7
2. पूँजी प्राप्तियां	14.6	20.2	78.0	84.0	18.7	24.0	-27.6	-41.0
2.1. ऋण की वसूली	11.4	13.2	28.0	23.0	40.8	57.5	-13.5	37.7
2.2. अन्य प्राप्तियां	3.2	7.0	50.0	61.0	6.3	11.4	-54.4	-71.7
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	1637.0	1417.3	3207.2	2716.3	51.0	52.2	15.5	17.7
4. राजस्व व्यय	1696.5	1628.5	3709.4	3502.1	45.7	46.5	4.2	10.0
जिसका कि								
(i) ब्याज भुगतान	515.0	484.3	1162.9	1080.0	44.3	44.8	6.3	10.9
5. पूँजीगत व्यय	415.0	490.6	1111.1	1001.0	37.3	49.0	-15.4	43.1
जिसका कि								
(ii) ऋण और अग्रिम	55.4	74.8	192.4	163.8	28.8	45.7	-25.9	217.5
6. कुल व्यय (4+5)	2111.5	2119.1	4820.5	4503.1	43.8	47.1	-0.4	16.2
7. राजस्व घाटा (4-1)	74.2	231.4	580.2	869.9	12.8	26.6	-68.0	-25.6
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	474.5	701.9	1613.3	1786.8	29.4	39.3	-32.4	13.2
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	-40.5	217.5	450.4	706.8	-9.0	30.8	-118.6	18.8

स्रोत: लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी II: केंद्र सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वास्तविक आंकड़े				बीई का प्रतिशत				वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	तिल		तिल		तिल		तिल		2024-25	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	Q1	Q2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियां	829.7	588.6	792.7	808.5	26.5	22.4	25.3	30.7	41.0	-2.0
1.1. निवल कर राजस्व	549.6	433.6	715.5	726.7	21.3	18.6	27.7	31.2	26.8	-1.5
1.2. गैर-कर राजस्व	280.0	155.0	77.2	81.8	51.3	51.4	14.1	27.1	80.7	-5.7
1.3. व्याज प्राप्तियां	11.7	9.5	8.6	7.8	30.6	38.5	22.6	31.3	22.7	11.3
2. पूँजी प्राप्तियां	4.5	10.7	10.1	9.5	5.8	12.7	12.9	11.3	-57.8	6.5
2.1. ऋण की वसूली	4.5	6.5	6.9	6.7	16.1	28.1	24.7	29.3	-30.2	2.5
2.2. अन्य प्राप्तियां	0.0	4.2	3.2	2.7	0.0	6.9	6.3	4.5	-99.9	16.5
3. कुल प्राप्तियां (1+2)	834.2	599.3	802.8	818.0	26.0	22.1	25.0	30.1	39.2	-1.9
4. राजस्व व्यय	788.9	772.2	907.7	856.3	21.3	22.0	24.5	24.5	2.2	6.0
जिसका कि										
(i) व्याज भुगतान	264.1	243.7	251.0	240.6	22.7	22.6	21.6	22.3	8.3	4.3
5. पूँजीगत व्यय	181.1	278.5	233.9	212.1	16.3	27.8	21.1	21.2	-35.0	10.3
जिसका कि										
(i) ऋण और अग्रिम	30.0	44.6	25.4	30.2	15.6	27.2	13.2	18.4	-32.7	-16.0
(ii) पूँजीगत परिव्यय	151.0	233.9	208.5	181.9	16.4	27.9	22.7	21.7	-35.4	14.6
6. कुल व्यय (4+5)	969.9	1050.7	1141.6	1068.5	20.1	23.3	23.7	23.7	-7.7	6.8
7. राजस्व घाटा (4-1)	-40.8	183.6	115.0	47.8	-7.0	21.1	19.8	5.5	-122.2	140.5
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	135.7	451.4	338.8	250.5	8.4	25.3	21.0	14.0	-69.9	35.3
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	-128.3	207.7	87.9	9.9	-28.5	29.4	19.5	1.4	-161.8	790.3

स्रोत: लेखा महानियंत्रक कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी III: अप्रैल-सितंबर के दौरान राज्य सरकारों की बजटीय स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वार्षिक आकड़े		बजट अनुमान		बीई का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	1508.4	1403.2	3869.1	3573.7	39.0	39.3	7.5	7.1
1.1. कर राजस्व	1292.7	1156.6	3044.1	2686.9	42.5	43.0	11.8	14.6
1.2. गैर-कर राजस्व	83.9	91.3	276.8	245.5	30.3	37.2	-8.1	18.5
1.3. अनुदान सहायता एवं अंशदान	131.8	155.2	548.2	641.2	24.0	24.2	-15.1	-30.7
2. पूँजी प्राप्तियां	2.4	3.3	25.8	24.2	9.3	13.6	-27.3	16.9
2.1 क्रण और अग्रिम की वसूली	2.3	3.2	20.2	17.8	11.5	18.0	-27.6	17.8
2.2. अन्य प्राप्तियां	0.1	0.1	5.6	6.4	1.2	1.3	-16.6	-9.5
3. कुल प्राप्तियां	1510.8	1406.5	3894.9	3597.9	38.8	39.1	7.4	7.1
4. राजस्व व्यय	1681.0	1525.0	4038.9	3695.9	41.6	41.3	10.2	8.5
4.1 व्याज भुगतान	220.8	194.1	503.2	459.2	43.9	42.3	13.7	12.5
5. पूँजीगत व्यय	233.8	251.1	777.2	734.9	30.1	34.2	-6.9	44.4
5.1 पूँजीगत परिव्यय	202.5	230.3	706.1	658.9	28.7	34.9	-12.1	51.5
6. कुल व्यय	1914.8	1776.1	4816.1	4430.8	39.8	40.1	7.8	12.5
7. राजस्व घाटा (4-1)	172.6	121.8	169.7	122.3	101.7	99.6	41.7	27.5
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	404.0	369.6	921.2	833.0	43.9	44.4	9.3	38.6
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	183.2	175.5	418.0	373.8	43.8	46.9	4.4	86.7

नोट: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; तथा राज्यों के बजट दस्तावेज़।

सारणी IV: राज्य सरकार के वित्त की तिमाही स्थिति

मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वार्षिक आकड़े				बजट अनुभान				वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर	
	ति�1		ति�2		ति�1		ति�2		2024-25	
	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	2024-25	2023-24	Q1	Q2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियां	736.7	722.8	771.7	680.4	19.0	20.2	19.9	19.0	1.9	13.4
1.1. कर राजस्व	652.7	560.5	640.0	596.1	21.4	20.9	21.0	22.2	16.4	7.4
1.2. गैर-कर राजस्व	40.5	35.9	43.4	55.4	14.6	14.6	15.7	22.6	12.8	-21.7
1.3. अनुदान सहायता एवं अंशदान	43.4	126.4	88.3	28.9	7.9	19.7	16.1	4.5	-65.6	206.0
2. पूंजी प्राप्तियां	1.2	1.7	1.2	1.6	4.6	6.8	4.6	6.7	-27.5	-27.1
2.1 ऋण और अधिम की वसूली	1.2	1.6	1.2	1.6	5.8	8.9	5.7	9.0	-26.9	-28.3
2.2. अन्य प्राप्तियां	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.3	-45.3	67.8
3. कुल प्राप्तियां	737.9	724.5	772.9	682.0	18.9	20.1	19.8	19.0	1.9	13.3
4. राजस्व व्यय	776.3	713.1	904.7	811.9	19.2	19.3	22.4	22.0	8.9	11.4
4.1 ब्याज भुगतान	95.3	80.8	125.5	113.3	18.9	17.6	24.9	24.7	17.9	10.8
5. पूंजीगत व्यय	79.7	99.7	154.1	151.4	10.3	13.6	19.8	20.6	-20.1	1.8
5.1 पूंजीगत परिव्यय	68.5	88.5	134.0	141.8	9.7	13.4	19.0	21.5	-22.6	-5.5
6. कुल व्यय	855.9	812.8	1058.8	963.3	17.8	18.3	22.0	21.7	5.3	9.9
7. राजस्व घाटा	39.6	-9.7	133.0	131.5	23.3	-8.0	78.3	107.6	-506.8	1.1
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	118.1	88.3	285.9	281.3	12.8	10.6	31.0	33.8	33.7	1.7
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	22.8	7.5	160.4	168.0	5.4	2.0	38.4	44.9	203.7	-4.5

नोट: डेटा 22 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक; तथा राज्यों के बजट दस्तावेज़।